भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 741
गुरुवार, 23 जुलाई, 2026/1 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान योजना के अंतर्गत मार्ग

741. **श्री कार्ती पी. चिदम्बरमः**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ान योजना के अंतर्गत वर्तमान में प्रचालनशील मार्गों की राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या कितनी है और योजना शुरू होने के बाद से लाभ में कमी के कारण बंद किए गए मार्गों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में इस योजना के अंतर्गत एयरलाइन संचालकों को संवितरित कुल व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने टियर-2 और टियर-3 शहरों में हवाई संपर्क पर उड़ान योजना के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो इसके मुख्य परिणाम क्या रहे हैं;

(घ) निरंतर सब्सिडी पर निर्भर रहे बिना प्रादेशिक मार्गों पर संधारणीय लाभ सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) अभी भी कम हवाई संपर्क वाले पर्वतीय और उत्तर-पूर्वी राज्यों में उड़ान योजना का विस्तार करने के लिए क्या समय-सीमा नियत की गई है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) – 'उड़ान' की शुरुआत के बाद से, 679 आरसीएस मार्गों को प्रचालनरत किया गया है, जिनमें से 348 मार्ग वर्तमान में कार्यशील हैं। उन मार्गों का राज्य/संघ राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में है, जो आरसीएस अवधि के पूर्ण होने से पहले बंद कर दिए गए थे और वर्तमान में विभिन्न कारणों से प्रचालनरत नहीं हैं। वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान एयरलाइनों को कुल संवितरित वीजीएफ क्रमशः 807.02 करोड़ रुपये, 628.42 करोड़ रुपये और 738.13 करोड़ रुपये (अनंतिम) था।

(ग): 'उड़ान' योजना के प्रभाव का मूल्यांकन निम्नलिखित अध्ययनों के माध्यम से किया गया है:

i. इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) की रिपोर्ट "क्षेत्रीय संपर्क योजना 'उड़ान' - प्रगति और संभावनाएं", (2021-22)

ii. डीएमईओ नीति आयोग द्वारा "क्षेत्रीय संपर्क योजना का मूल्यांकन अध्ययन" योजना के लिए मध्यावधि मूल्यांकन (2023-24)

(घ) और (ङ): 'उड़ान' योजना का अगला चरण दिनांक 04.07.2026 को शुरू किया गया, और इसे वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक 28,840 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें पर्वतीय, उत्तर-पूर्वी और आकांक्षी (एचआईएनईआर) राज्यों/जिलों में 200 हेलीपोर्टों के विकास के लिए 3,661 करोड़ रुपये शामिल हैं। समय के साथ-साथ वित्तीय सहायता पर निरंतर निर्भरता के बिना 'उड़ान' मार्गों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए, इस योजना में पाँच वर्ष तक बढ़ाए जा सकने वाले एक लंबी अवधि के वीजीएफ तंत्र को शामिल किया गया है, जिसे उत्तरोत्तर कम किया जा सकेगा ताकि एयरलाइनें वाणिज्यिक रूप से संवहनीय परिचालनों की ओर बढ़ सकें, जबकि संवहनीयता सुनिश्चित करने के लिए वीजीएफ के माध्यम से समर्थित सीटों हेतु 'उड़ान' योजना हवाई किराए की अधिकतम सीमा निश्चित की गई है।

अनुलग्नक

अवधि पूर्ण होने से पहले बंद किए गए आरसीएस मार्गों की राज्य/संघ राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बंद किए गए आरसीएस मार्गों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	3
2	अरुणाचल प्रदेश	3
3	असम	15
4	बिहार	3
5	छत्तीसगढ	4
6	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	2
7	गुजरात	11
8	हरियाणा	2
9	हिमाचल प्रदेश	5
10	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	1
11	झारखंड	3
12	कर्नाटक	12
13	मध्य प्रदेश	14
14	महाराष्ट्र	5
15	मणिपुर	1
16	मेघालय	2
17	ओडिशा	1
18	पंजाब	7
19	राजस्थान	11
20	सिक्किम	1
21	तमिलनाडु	2
22	तेलंगाना	3
23	उत्तर प्रदेश	34
24	उत्तराखंड	17
25	पश्चिम बंगाल	3

*****